केन्द्र सरकार की ओर से पूरी होगी। चूंकि नागपुर देश के मध्य में है। इससे चारों ओर आसानी से आवागमन हो सकता है, आना जाना हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि नागपुर पैसेंजर और कारगो दोनों का एक हब बने।

श्री सभापति: क्या आप कोई डेफिनेट बात कह सकते हैं?

श्री प्रफुल्ल पटेल: माननीय सदस्य महोदय से मैं यह कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कारगो हब के बारे में...

श्री सभापति: चलो छोड़ो।

श्री प्रफुल्ल पटेल: आपने जो बात रखी है, महाराष्ट्र सरकार जो बात कहती आ रही है, यह टॉप प्रायोरिटी पर हमारे मंत्रालय में है।

Nationalisation of Rural Banks

*25. SHRIMATI JAMANA DEVI BARUPAL†:
DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether rural bank employees have asked the Central Government to nationalize rural banks with a view to effectively increasing rural credit in villages and to save farmers from the debt trap;

(b) whether rural banks were promoted with an aim to support small and marginal farmers and artisans in villages and were made to extend credit to affluent customers under the supervision of commercial banks;

(c) if so, whether Government have considered their suggestions; and

(d) if so, what steps are being taken to improve rural banking in the country?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Employees Associations/Unions of Regional Rural Banks have been suggesting the following for restructuring/reorganization of Regional Rural Banks (RRBs).

(i) Recapitalisation of RRBs:

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Jamana Devi Barupal.

(ii) Delinking of RRBs from Sponsor Banks.

(iii) Amalgamation of RRBs at State/Zonal level under National Rural Bank or NABARD.

(iv) Majority shareholding in RRBs by the Central Government

(v) Implementation of the Government sponsored programmes, credit to SHGs and credit for farm sector and other rural infrastructure programmes through RRBs.

(b) Regional Rural Banks Act, 1976 envisaged setting up of RRBs as low cost rural credit institutions to develop rural economy by providing rural credit and other facilities, particularly to small and marginal farmers, agricultural labour, artisans and small entrepreneurs for development of agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities. RRBs were initially allowed to lend only to the target group comprising small and marginal farmers, landless labour, rural artisans and other weaker sections of the society. With a view to making RRBs financially viable they were allowed with effect from 1992 to lend to non target groups to the extent of 40% of their fresh lending. This limit was subsequently raised to 60% in 1994. However, with effect from 2003-04, RRBs are required to achieve a lending target of 60% for the priority sector. Further, of the total priority sector advances, atleast 25% (that is 15% of the total outstanding advances) should be advanced to weaker sections of the society.

(c) and (d) The suggestions being considered for restructuring of RRBs include:—

(i) Merger with Sponsor Banks.

(ii) All RRBs sponsored by as Sponsor Bank to be amalgamated into a single wholly-owned subsidiary of that sponsor bank.

(iii) Each RRBs to be a wholly-owned subsidiary of its sponsor bank.

(iv) Consolidation of all RRBs into a National Rural Bank.

(v) Amalgamation of RRBs into zonal banks.

(vi) Maintaining *Status-quo*.

Each of the above options has certain merits and demerits and none can be applied in isolation because of the prevailing diverse socio-

economic conditions and region-specific problems. A hybrid model combining several options has to be evolved which may involve extensive amendments in the RRBs Act. Discussions in this regard had so far remained inconclusive.

RRBs with their extensive network of branches can play a key role in providing rural credit. Government has therefore decided to support a programme for improving their health and effectiveness.

श्रीमती जमना देवी बारुपाल: सभापति महोदय, मेरे प्रश्न संख्या-25 का उत्तर तो करीब-करीब लिखित रूप में आ गया है लेकिन फिर भी मैं आप से आग्रह करूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत किसानों और कारीगरों को बैंकों से ऋण लेने में जो असुविधा होती है क्या उसका सरलीकरण किया जाएगा? ऋण के ब्याज को कम करते हुए चार व पांच प्रतिशत करने का क्या सरकार कोई विचार रखती है ताकि किसान समृद्ध हो सकें?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, the Government is fully alive to the problem of agricultural credit and that is why, Sir, you will recall that one of the first major announcements of this Government was made on 18th June of this year when we made a detailed policy statement on the flow of agricultural credit. I am confident, Sir, that the target that we have set for commercial banks, RRBs and co-operative banks will be met this year. As far as price is concerned, we leave pricing to the banks, although there are indicative guidelines by NABARD, by the RBI and by the Indian Banks' Association. If the cost of funds to the lending instituiions comes down, then, surely, the interest rates will also come down. But on a matter of price, I respectfully submit that we should leave it to the lending institutions and hope that the lending institutions will be able to lend at the lowest possible interest rate to all bodies.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I am fully satisfied with the two-page written reply of the Minister. No answer. *(Interruptions)*.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: No answer! *(Interruptions)*... No questions. *(Interruptions)*.

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: सर, वे परेशान होकर आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, यह बताइए?

श्री सभापति: उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं?...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: उनको बहुत परेशानी होती है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, मैं आपको भी याद दिलाना चाहूंगी और पूरे इस सदन को भी याद दिलाना चाहूंगी कि इस एक मुद्दे को एक नहीं अनेकों बार मैंने इस सदन में उठाया है और माननीय सदस्यों ने भी उठाया है। महोदय, आपको याद होगा कि आपने स्वयं इस बात को यहां इस सदन में उठाया था कि इस मांग को मान लिया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि निश्चित रूप पिछली सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जिस राह पर ले गई थी वह बहुत ही खराब रास्ता था। उसके चलते हमारी खेती का जो कारपोराइजेशन हो रहा था, जो निगमीकरण हो रहा था जिसके चलते हमारे ग्राम शहरों के उपनिवेश जैसे बनते जा रहे थे। सी॰डी॰आर॰ रेशो इसका उदाहरण हैं सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगी कि रीजनल रूरल बैंक एम्प्लाइज एसोसिशन ने एक बार नहीं, अनेकों बार इस मांग को लेकर संसद के सामने धरने दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं, भूख-हड़ताल की है। माननीय मंत्री जी मैं आपसे यह वादा लेना चाहूंगी कि नई सरकार ने, और विशेषकर प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा को, जो पिछली सरकार की दिशा थी, उस दिशा को मोड़ते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा बल देने की बात कही है ताकि हम अपने गांवों को इस बर्बादी से बचा सकें। सभापति महोदय, आंकड़ों के अनुसार, यह आंकड़ों में आया है कि हर वर्ष बीस लाख किसान अपनी जमीन खोकर खेत मजदूर बनते जा रहे हैं। इसलिए रीजनल रूरल बैंक एम्पलोइज एसोसिएशन की ग्रामीण बैंकों को पुनर्गठित करने की जो मांग है कि एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाया जाए...(व्यवधान)

श्री सभापति: क्वेश्चन पूछिए, भाषण मत कीजिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाने की जो मांग है, आप उस मांग पर कितने गंभीर हैं और उस मांग को आप कब तक मान लेंगे ताकि गांव में सी॰डी॰आर॰ रेशो बढ़े और हमारे किसानों को ऋण की सुविधा मिले।

श्री मंगनी लाल मंडल: सभापति जी, मैं नया सदस्य हूं। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य: पहले जवाब दे दें।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Mr. Chairman, Sir, if I have understood the question of the hon. Member correctly, she wishes to know as to when we will accept the suggestion to set up a national rural bank. My respectful submission, through you, to the house is that that does not appear to be the correct solution to the problem. Setting up a national rural bank, in my respectful submission, does not appear to be the answer to the problem. Today, approximately 150 of the RRBs have become profitable and the remaining are not yet profitable. In terms of accumulated losses, nearly 97 RRBs have accumulated losses. Each RRB is under a sponsored bank. I am taking steps to ensure that the sponsored banks are held squarely accountable for the performance of the RRBs. With good governance and adherence to good financial discipline, it is possible to

turn around RRBs. We have done so by recapitalising a large number-of RRBs. There are atleast three reports with the Government. I will consider all that in the next few months and we will find solutions. But to say that establishing a national rural bank will be the correct answer, with great respect, I do not share that opinion.

श्री मंगनी लाल मण्डल: सभापति महोदय, यह प्रश्न मूल है। छोटे और सीमांत किसानों, गांव के जो कारीगर हैं, उनको ऋण प्रदान करने के लिए है। सरकार ने इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहमति से सर्विस एरिया घोषित किया है। यहां वाणिज्यिक बैंक और आर.आर.बी. की चर्चा है। जो सर्विस एरिया है, सरकार ने उसको लागू करने के लिए क्रेडिट प्लान की घोषणा की है। जितनी भी सहायता की, ऋण की योजनाएं हैं, वे सभी क्रेडिट प्लान के माध्यम से लागू की जाती हैं लेकिन आर०आर०बी० को कुछ छूट दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा ऋण देने के लिए जो घोषित कार्यक्रम है, एक ही सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंक को ऋण देने के सारे अधिकार दिए गए हैं लेकिन इस देश में आर०आर०बी० को सर्विस एरिया से कहीं-कहीं, खासकर के बिहार में छोड़ दिया गया है। उदाहरणस्वरूप प्रधानमंत्री रोजगार योजना और किसानों का जो क्रॉप ऋण है, वह आर०आर०बी० के सर्विस एरिया में नहीं आता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कमर्शियल बैंक का जो सर्विस एरिया है और आर०आर०बी० का जो सर्विस एरिया है, क्या उन दोनों की एकरूपता पर सरकार विचार करना चाहेगी और इसकी कोई व्यवस्था करना चाहेगी?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, each RRB is confined to one State. Now, the RRBs may have a number of branches. So, an RRB will have to lend within that State; or, each branch of an RRB will have to lend within the area carved out by the Head Office of the RRB. Now, the commercial banks are a separate system of banks. The commercial banks also have regional offices and head offices in the States. And, they have a number of brances in the States. And, I don't think it is possible to integrate the service area of RRBs with commercial banks. In fact, I don't even think this will be a wise idea. The RRBs are essentially lending to specified target groups so that the commercial banks have a much wider range of customers. So, I am not sure what the hon. Member wishes me to do. But I don't think it is possible to integrate or bring a certain amount of parity between the service area of a RRB and the service area of a commercial bank.

श्री मंगनी लाल मण्डल: महोदय...

श्री सभापति: नहीं, आप बैठिए। देखिए, पहली बार मैंने आप को चांस दिया है, अब अगर आप पहली बार ठीक ढंग से behave नहीं करेंगे तो आइंदा ध्यान रखूंगा।

*26. [*The questioner (Shri S.M. Laljan Basha) was absent. For answer vide Pages 29-30.*]